

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक: २ / दिसम्बर २०११

विषय:- श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट, हरिद्वार को ग्राम बढेडी राजपूतान, परगना एवं तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल ०.३२०० है० भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२३२/भूमि व्यवस्था-भूमि क्रय, दिनांक-२७.११.२००९ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट, हरिद्वार को ग्राम बढेडी राजपूतान, परगना एवं तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल ०.३२०० है० भूमि क्रय करने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(III) के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के दृष्टिगत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुत खाता खसरा सं० के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- १- क्रेता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- २- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- ३- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षण संस्थान) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-१६७ के परिणाम लागू होंगे।
- ४- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- ५- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क़य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

8- किसी भी दशा में प्रस्तावित क़ेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क़य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

11- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

12- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत आदेश की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0- / 45 / 18(2) / 2011-1(98) / 2011 / सम्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- अध्यक्ष, श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम बढेडी राजपुतान, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सतोष बडोनी)
अनुसचिव।